

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

अपील प्र० क० 1736-एक/2001 विरुद्ध आदेश दिनांक 22-08-01 पारित आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 180/1997-98 अपील.

- 1- दीनानाथ केशरवानी तनय लखनलाल केशरवानी
लाल मुकाम दादर, तह० हुजूर, जिला रीवा
- 2- शिवकुमार मिश्र तनय जगतदेव प्रसाद मिश्र
नि० ग्राम धवैया, तह० हुजूर, जिला रीवा

--- अपीलाधीगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

-- उत्तरवादी

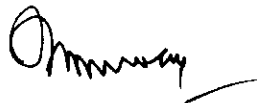
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक - आवेदकगण
श्री डी०के० शुक्ला, पैनल अभिभाषक- अनावदेक शासन

आदेश

(आज दिनांक 1-5-2014 को पारित)

यह अपील का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 180/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-08-2001 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

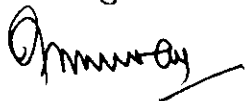
2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला रीवा द्वारा संहिता की धारा 247(7) के



अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया और अपीलार्थीगण को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 27-6-98 द्वारा अपीलार्थीगण को 400 टक सोलिंग पत्थर के अवैध उत्खनन का का स्टॉक पाया गया। अतः अपर कलेक्टर ने अपीलार्थीगण पर अवैध उत्खनित खनिज के बाजार मूल्य रू. चार लाख की दुगुनी राशि रू. आठ लाख का अर्थदण्ड आरापित कर जप्त सामग्री राजसात करने का आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील आयुक्त, रीवा संभाग ने अपने आदेश दिनांक 22-8-01 द्वारा खारिज की। अतः अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

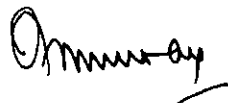
3/ मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण के अभिभाषक का तर्क है कि अपीलार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अवैध उत्खनन नहीं किया गया है। पटवारी एवं खनिज निरीक्षक के कथनों से भी अपीलार्थीगण द्वारा अवैध उत्खनन करना प्रमाणित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अवैध उत्खनन स्थल की जाँच नहीं की गयी और ना ही माप की गयी है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि जिस भूमि पर अवैध उत्खनन होना पाया गया उसके अभिलिखित भूमिस्वामियों को ना तो पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सूचना दी गयी। अतः उन्होंने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4/ उत्तरवादी शासन के अभिभाषक का तर्क है कि खनिज का अवैध उत्खनन कर 400 टक सोलिंग का स्थल निरीक्षण के दौरान स्टॉक पाया गया। अपर कलेक्टर ने विधिवत कारण बताओ सूचनापत्र अपीलार्थीगण को तामील किये गये हैं, किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे प्रश्नाधीन उत्खनन को वैध होना मान्य



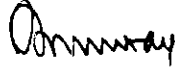
किया जा सके। इसके विपरीत शासकीय साक्षी खनिज निरीक्षक एवं पटवारी की साक्ष्य से अवैध उत्खनन करना प्रमाणित है। अतः उन्होंने द्वितीय अपील में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं होने से अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अपर कलेक्टर के अभिलेख से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अपीलार्थीगण को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किये हैं। अपीलार्थी दीनानाथ तनय लखनलाल द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र का जबाव भी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने उत्खनन से इन्कार नहीं किया है, बल्कि यह दर्शाया है कि अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्र में से 400 मे.टन पत्थर निकाला था जिसका स्टॉक ख.नं. 1344/2, 1344/3 एवं 1344/3/2 ग्राम दादर में था जिसकी पूर्ण रायल्टी जिला कार्यालय खनिज शाखा में जमा है व खनिज शाखा द्वारा स्टॉक का निरीक्षण कर रायल्टी का असेसमेंट किया जा चुका है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना अभिलेख से विदित नहीं होता। अपीलार्थी द्वारा जबाव के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से विदित होता है कि अपीलार्थी को खसरा नं0 1326, 1327, 1344/3 एवं 1375/1 कुल रकबा 8.81 का 5-1-94 को एक वर्ष के लिये उत्खनिज पट्टा प्रदत्त किया गया था, किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा भूमि क0 1344/2 3.00 एकड़, 1344/3/1 1.17 तथा 1344/3/2 1.83 से 400 टक सोलिंग का अवैध उत्खनन करने से बाजार मूल्य से दुगनी राशि अर्थात् आठ लाख रुपये शास्ती आरोपित की गयी है जिसे साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को स्वीकृत क्षेत्र से उत्खनन करना नहीं माना जा सकता। शासन की ओर से अपर कलेक्टर द्वारा खनिज निरीक्षक अनरुद्ध सिंह तथा हल्का पटवारी सत्यभान के कथन लिपिबद्ध किये हैं जिन्होंने प्रश्नाधीन अवैध उत्खनित खनिज के स्टॉक



की पुष्टि की है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में द्वितीय अपील में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील खारिज की जाती है। आयुक्त का आदेश दिनांक 22-8-01 तथा अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 27-06-98 यथावत रखे जाते हैं।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य, 11/5/14
राजस्व मण्डल, म०प्र०